

रियल एस्टेट से रिटेल को नई रफ्तार

रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में 57 प्रतिशत रिट्स और इनविट्स का हिस्सा है

नयी दिल्ली, 21 नवंबर. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (रिट्स) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) में खुदरा निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए शुक्रवार को कहा कि ये दोनों तंत्र देश की बुनियादी ढांचा जरूरतों के लिए जैसे जुटाने का अनोखा अवसर प्रदान करते हैं।



भारत इनविट्स एसोसिएशन और इंडियन रिट्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने बताया कि सेबी दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश

बढ़ाने के उपाय कर रहा है. इसके लिए वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा कर रहा है. उन्होंने एमएससीआई की तरह दूसरे सूचकांकों में इन्हें अधिक से अधिक शामिल करने की जरूरत पर बल दिया.

वैश्विक स्तर पर जहां सभी सूचीबद्ध रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में 57 प्रतिशत रिट्स और इनविट्स का हिस्सा है, वहीं भारत में यह महज 12 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि दोनों तंत्र देश में नये हैं और इन्हें बढ़ावा देने के उपाय किये जाने चाहिये. सेबी ने पेंशन फंड नियामक और बीमा नियामकों से उनके द्वारा नियमित इकाइयों को इनविट्स और रिट्स में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की.

कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार को परिसंपत्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाने की बजाय इनविट्स बनाकर उसके मोदीकरण को सरल बनाने पर विचार करना चाहिये.

उन्होंने कहा कि भारत के पास रिट्स और इनविट्स मिलाकर एक लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 90 लाख करोड़ रुपये के

निवेश तक पहुंचने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश में पांच सूचीबद्ध रिट्स और 24 सूचीबद्ध इनविट्स हैं. इनके पास सम्मिलित रूप से 9.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश है. इसमें सात लाख करोड़ रुपये का निवेश इनविट्स के पास है. श्री पांडेय ने कहा कि आने वाले समय में देश में सड़क, परिवहन, शहरीकरण, ऊर्जा और विमानन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं.

रुपया पहली बार 89 रुपए प्रति डॉलर के पार लुढ़का

मुंबई, 21 नवंबर. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में शुक्रवार को बीच कारोबार में रुपये में भारी गिरावट देखी गयी और यह बीच कारोबार में पहली बार 89 रुपये प्रति डॉलर के पार लुढ़क गया. खबर लिखे जाते समय भारतीय मुद्रा 81.50 पैसे टूटकर 89.50 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक कमजोर हो चुकी थी. ये आंकड़े अर्न्तगत हैं. पिछले कारोबारी दिवस पर रुपया 88.6850 रुपये प्रति डॉलर रहा था. आज यह एक पैसे की बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में 89.50 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. दोपहर बाद यह काफी तेजी से अचानक 89 रुपये प्रति डॉलर के पार लुढ़क गया. रुपये की गिरावट में शेर बाजार की बिकवाली और दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर की तेजी का भी योगदान रहा.

भारत ने शेयर बाजार मंडप किया स्थापित

2025 में सेबी के मंडप का उद्घाटन सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने किया था

नई दिल्ली, 21 नवंबर. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) एक वार्षिक, बड़े पैमाने का बी2बी और बी2सी कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है.



भारत के सुव्यवस्थित प्रतिभूति बाजार को प्रदर्शित करने और वित्तीय साक्षरता एवं निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बीएसई, एनएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, एएमएफआई, एनआईएसएम, एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स, सीएएमएस और केफिन टेक्नोलॉजिज के सहयोग से, 14-

27 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में भारत का शेयर बाजार नामक एक मंडप स्थापित किया है.

इस वर्ष के मंडप का विषय विकसित भारत का आधार, भारत का शेयर बाजार आईआईटीएफ के समग्र विषय एक भारत, श्रेष्ठ भारत

से काफी मेल खाता है जो पूरे देश में एकता, प्रगति और वित्तीय सशक्तिकरण का जश्न मनाता है. इस मंडप का उद्घाटन 14 नवंबर, 2025 को तुहिन कांत पांडे, अध्यक्ष, सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों की उपस्थिति में किया गया.

रेलवे राजमार्ग की तीन परियोजनाओं का मूल्यांकन

नयी दिल्ली, 21 नवंबर. प्रधानमंत्री गतिशक्ति वृद्ध योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना समूह (एनपीजी) की 102वीं बैठक में गुरुवार को रेलवे और राजमार्ग क्षेत्र की तीन प्रमुख परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेल मंत्रालय की ओर बिहार और असम से जुड़ी दो परियोजनाओं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की महाराष्ट्र से जुड़ी एक परियोजना का मूल्यांकन किया गया. रेल मंत्रालय ने बिहार में पुनारख और किऊल स्टेशनों के

बीच लगभग 49.57 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है. प्रस्तावित खंड पटना और लखीसराय जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य के प्रमुख औद्योगिक एवं कृषि गलियारों में रेल अवसरचना मजबूत होगी.

इससे विशेष रूप से पटना, फतुहा, बख्तियारपुर और मोकामा जैसे केंद्रों को लाभ होगा, जिससे यात्री एवं माल ढुलाई दोनों में मदद मिलेगी. बैठक में असम में सिलघाट और देकारगांव के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव का भी मूल्यांकन किया गया. यह 27.50 किलोमीटर की लाइन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित स्टेशन को जोड़ेगी.

सांस्कृतिक अध्ययन के लिए 100 करोड़ देगा अडानी समूह

अहमदाबाद, 21 नवंबर. अडानी समूह भारतीय उपमहाद्वीप - विशेषकर भारत - के इतिहास, यहां की संस्कृति और विरासत (इंडोलॉजी) के अध्ययन के लिए काम करने वाले विद्वानों और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को 100 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा. समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने शुक्रवार को अडानी वैश्विक इंडोलॉजी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत नॉलेज ग्राफ बनाने और इंडोलॉजी मिशन में काम करने वाले विद्वानों और विशेषज्ञों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता की घोषणा की. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चे अपने देश के बारे में जानने के लिए न तो किताबों के पन्ने पलटेंगे और न ही किसी जानकार के पास जायेंगे.

गोयल ने इजरायल के मंत्रियों के साथ की बैठक

व्यापार और आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की समिति की महत्वपूर्ण मीटिंग में कई प्रस्ताव पास

नयी दिल्ली, 21 नवंबर. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल की तीन दिनों की अपनी पहली सरकारी यात्रा के पहले दिन गुरुवार को तेल अवीव में वहां के अर्थव्यवस्था और उद्योग मामलों के मंत्री नीर बरकत और वित्त मंत्री बेजालेल योयेल स्मोत्रिख से अलग अलग भेंट की तथा व्यापार और आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की. श्री गोयल ने श्री बरकत के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोशल मीडिया पर कहा, तेल अवीव में इजरायल के



अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों की अलग अलग क्षेत्रों में मजबूती एक दूसरे के बीच के व्यवसायियों के बीच सहयोग के

रास्ते बना सकती है. वित्त मंत्री स्मोत्रिख के साथ बैठक के बारे में श्री गोयल ने एक अलग पोस्ट में कहा, इजराइल के वित्त मंत्री स्मोत्रिख के साथ एक अच्छी मुलाकात हुई.

इस कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था और उद्योग मामलों के मंत्री श्री बरकत भी शामिल थे. श्री गोयल ने इस कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं पहली बार तेल अवीव आकर बहुत खुश हूँ. मेरा पहला कार्यक्रम इंडिया-इजराइल बिजनेस समिट में वृद्धि का प्रवेश द्वार विषय पर मेरे दोस्त और इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मामलों के मंत्री नीर बरकत के साथ व्याख्यान था.

डिजिटल समय में साहित्य और कलाएं

फिल्महाल जब मैं डिजिटल समय में साहित्य और कलाओं की स्थिति पर विचार कर रहा हूँ तो बरबस ही चालीस के दशक में वाल्टर बेंजामिन द्वारा लिखित लंबे आलेख 'आर्ट इन द इरा ऑफ मैकेनिकल रिप्रॉडक्शन' (यांत्रिक पुनरुत्पादन के समय में कलाएं) की याद आ गई है. प्रिंटिंग प्रेस तब तक व्यापक रूप से प्रचलन में आ

गई थी जिसने पेंटिंग्स का बड़े पैमाने पर मुद्रण संभव बना दिया था. जिस कला का आस्वाद पहले संग्रहालयों में या चित्रकार के निवास पर जाकर घंटों उसे निहारते हुये किया जाता था, अब वह फ्रिटेड स्वरूप में आस्वाद के घर तक पहुंच गई थी और शायद उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही थी. वह उसे कभी भी देख सकता था, उसके आस्वाद का समय और तरीका अब निश्चित नहीं रहा था. बेंजामिन का मानना था कि इससे कलात्मक आस्वाद की जनतांत्रिकता तो बढ़ी थी

लेकिन उसकी गुणवत्ता का ह्रास हुआ था. आगे चलकर यही संगीत के साथ हुआ. ऑडियो टेक्नॉलॉजी के आने के बाद संगीत के आस्वाद का तरीका बदल गया. भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में कहा जाये तो लंबी-लंबी बैठकों का प्रचलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया. रिकॉर्ड्स जब तक डिस्क पर थे तब तक भी वे उच्च वर्ग की ही पहुंच में आते थे. पर फिर उनके कैसेट्स पर और वहाँ से सी.डी. पर और फिर वहाँ से प्ले ड्राइव पर और उससे भी आगे बढ़कर अब क्लाउड पर आने के बाद संगीत की

सोने में उछाल, चांदी सस्ती

नई दिल्ली, 21 नवंबर. शादी का सीजन शुरू होते ही देशभर में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलने लगी है. 21 नवंबर 2025 को सोने की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है, जबकि चांदी के भाव में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली. 24 कैरेट सोना 22 रुपये प्रति ग्राम महंगा होकर 12,448 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी 4,000 रुपये टूटकर 1,61,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. देश के ज्यादातर शहरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, पटना, लखनऊ और अन्य कई जगहों पर आज गोल्डरेट में हल्की बढ़त दर्ज की गई.

एसएफआईओ ने जारी किया क्यूआर कोड

नयी दिल्ली, 21 नवंबर. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जारी नोटिसों पर अब क्यूआर कोड का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से आसानी से इनका सत्यापन किया जा सकेगा. कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत गठित नोटिसों पर आसान सत्यापन के लिए होगा क्यूआर कोड

एसएफआईओ कानून की धारा 212 के तहत सौंपे गये गंभीर और बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है और उन पर केस चलाता है. जांच के दौरान, नियमों के मुताबिक समन/नोटिस भी जारी किया जाता है. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने शक्रवार को बताया कि एसएफआईओ ने समन/नोटिस के गलत इस्तेमाल या नकल को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया के

कोटक महिंद्रा बैंक ने की शेयर विभाजन की घोषणा

मुंबई, 21 नवंबर. निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने शुक्रवार को अपनी स्थापना दिवस पर शेयर विभाजन की घोषणा की. बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि उसके निदेशक मंडल ने पांच रुपये अंकित मूल्य वाले पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों को एक रुपये अंकित मूल्य वाले पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. उसने बताया कि इससे उसके शेयर आम निवेशकों के लिए और सुलभ होंगे. साथ ही, ज्यादा खुदरा निवेशकों के जुड़ने से बैंक को तरलता बढ़ाने में आसानी होगी.

समाचार विशेष

भाजपा में बड़े बदलाव की बयार!

जल्द होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान

लखनऊ. बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि किसी नए ओबीसी नेता को मौका मिल सकता है. इसके अलावा यूपी बीजेपी टीम में भी बड़ा बदलाव होगा. मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. निगम आयोग बोर्ड में भी संगठन में बदलाव के बाद तुरंत तैनाती होगी.

किसी नए ओबीसी नेता को मौका दिया जा सकता है. इन नेताओं में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम आगे है. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के नाम पर भी चर्चा में हैं. 98 में से 70 जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कोरम पूरा हो चुका है ऐसे में अब इसी महिने नाम की घोषणा हो सकती है.

अध्यक्ष के इंतजार में निगम, आयोग और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां भी अटक हुई हैं जो भी अगले महिने तक हो जाएंगी.

कांग्रेस का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है भाजपा

अगले दो वर्षों में विधायकों की संख्या 1800 से अधिक संभावित

जनता पार्टी के पास सर्वाधिक 1654 विधायक हो गए हैं.

पिछले कुछ साल में भाजपा ने देशभर के अलग-अलग राज्यों में विधायकों की जीत के साथ अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया है. भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राज्य विधानसभाओं में भाजपा का प्रदर्शन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसमें लगातार बढ़ोतरी जारी है.

मालवीय के अनुसार, अगले दो साल में भाजपा विधायकों की कुल संख्या 1800 को पार कर सकती है. मालवीय ने बताया कि कांग्रेस 1985 में लगभग 2,018 विधायकों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से

उपजी भारी सहानुभूति लहर जिम्मेदार थी. मालवीय ने कहा कि 1980 के दशक की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से सत्ता को मजबूत करना और मतदाताओं को प्रभावित करना आसान था.

मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद

इंफाल. भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद कर रही है. इस बार की कवायद को सीरियस बताया जा रहा है क्योंकि इस बार भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष खुद मणिपुर गए थे. उनके साथ पूर्वोत्तर में भाजपा का काम संभाल रहे लोकसभा सांसद संबित पात्रा भी मणिपुर गए थे. गौरतलब है कि इस साल के शुरू से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन

लगा हुआ है और विधानसभा निर्वाचित रखी गई है. लेकिन एक तो विधानसभा अंतकाल तक निर्वाचित नहीं जा सकती है और दूसरे डेढ़ साल के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है. तभी भाजपा के नेता इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे चुनाव की तैयारी करें या सरकार गठन इंतजार करें? पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अज्ञय भल्ला राज्य के राज्यपाल हैं.

असमजस में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष

भाजपा के 28 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही निर्णय होगा. ऐसे में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष भी असमजस में हैं कि उन्हें फिर मौका मिलेगा या उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष बनेगा. प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही यूपी से 80 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी होगी. संगठन-सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो गई है. हर महिने संगठन की सरकारी बैठक होगी. संगठन, विधायक, मंत्री और अफसर की बैठक होगी. समन्वय और समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी. पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी समय से नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश में है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पिछले साल जून में इस्तीफे की घोषणा की थी. उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया है. लेकिन अब इन्हें भी एक साल से अधिक समय हो गया है. लेकिन अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है.

विशेष भाजपा को हराना जरूरी, पर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी

कांग्रेस-उद्धव गुट में खुला टकराव

मुंबई. बिहार चुनाव नतीजों के बाद महा विकास आघाड़ी में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना गुट अब एक दूसरे पर सीधे सवाल उठा रहा है. पहले जो बातें बंद कमरों में होती थीं, अब वे खुलकर सामने दिखाई दे रही हैं. शिवसेना के मुखपत्र सामना में हाल ही में एक ओपिनियन छपा, जिसके बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस का कहना है कि अगर इसी तरह की बात जुलाई में ही साफ कर दी जाती, जब कहा गया था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की अब जरूरत नहीं है, तो हालात आज इतने उलझे हुए न होते.

कांग्रेस का तर्क है कि उस समय मनसे और उद्धव गुट की बढ़ती नजदीकियों की चर्चा भी चल रही थी. ऐसे में अगर शुरुआती दौर में ही साधियों को बता

दिया जाता कि राजनीतिक सोच में दूरी बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी अपनी भूमिका पहले ही तय कर लेती. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है. लेकिन तनाव तब बढ़ता है जब बातों को समय पर साझा नहीं किया जाता. उनके मुताबिक, शुरुआत में ही खुलकर बात दिया जाता कि आगे आकर इस तरह के सुझाव दिए जाएंगे, तो हर पार्टी अपने हिसाब से तैयारी कर लेती.

बिहार नतीजों पर कांग्रेस का बड़ा संदेश- कांग्रेस ने बिहार चुनाव परिणाम पर कहा कि ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ा इशारा है. उनकी दलील है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही नतीजा सामने आया था, और इस पेटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को हराना जरूरी है, यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं. लेकिन सिर्फ भाजपा का विरोध करना ही राजनीति नहीं है. उससे मुकाबला करते हुए अपने सिद्धांत छोड़ देना गलत होगा.

हिंसक और नफरत वाली राजनीति किसी भी तरफ की हो गलत है

कांग्रेस ने दोहराया कि उसकी नीति साफ है, वह किसी भी रूपा की हिंसा और नफरत की राजनीति के खिलाफ है. चाहे वह धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर. कांग्रेस का कहना है कि कानून हाथ में लेना किसी का भी हक नहीं है और इस सिद्धांत पर वह समझौता नहीं कर सकती. इसलिए भाजपा का विरोध करते हुए किसी दूसरी पार्टी की कट्टर या नफरत वाली राजनीति को सही ठहराना भी गलत है. कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा को हराने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है. यह असंवैधानिक फैसलों, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और कट्टर नीतियों के खिलाफ खड़े होने का नाम है.